

Developed India and 5 trillion dollar economy will be achieved through cooperation: Shah

विकसित भारत व 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था सहकारिता से मिलेगी : शाह

पीएम आवास योजना के तहत एक ही दिन में 20 लाख परिवारों के अपने घर का सपना साकार

अमर उजाला ब्यूरो

मुंबई। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने दो लक्ष्य तय किए हैं। पहला, 2047 तक विकसित भारत और दूसरा, 2027 तक 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था। ये दोनों लक्ष्य सहकारी क्षेत्र के योगदान से हासिल किए जा सकते हैं।

शाह ने पुणे में जनता सहकारी बैंक के होरक जयंती उत्सव के समापन समारोह को संबोधित किया। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत पहली बार एक साथ 20 लाख लाभार्थियों का खुद के घर का सपना पूरा हुआ। शाह ने पुणे में 20 लाख लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र व 10 लाख को पहली किस्त दी। इसके अलावा उन्होंने पुणे में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक की अध्यक्षता की। सहकारिता मंत्री ने कहा, जब तक हर परिवार में समृद्धि न हो तब तक विकसित भारत और 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था के संकल्प अधूरे हैं। इसलिए इस लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सहकारिता का योगदान बेहद महत्वपूर्ण है। शाह ने कहा कि पीएम मोदी अपने 10 साल के शासन में देश के 70 करोड़ लोगों के जीवन में बदलाव लाए। उन्होंने घर, बिजली, पानी, शौचालय, गैस, पांच लाख तक स्वास्थ्य बीमा और पांच किलो अनाज हर व्यक्ति को मुहैया कराया। शाह ने देशभर में सहकारी बैंकों को समर्थन देने के लिए एक बड़ी पहल पर चर्चा की। कहा, हम एक अंब्रेला संगठन को सक्रिय कर रहे हैं, जो सभी सहकारी बैंकों को हर संभव तरीके से मदद करेगा। अंब्रेला संगठन के लिए 300 करोड़ का बजट भी मंजूर किया गया है।



पीएम आवास योजना के तहत पुणे में लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपते गृह मंत्री शाह।

परिवर्तन लाने वाली संस्थाएं बनीं क्षेत्रीय परिषदें

शाह ने कहा कि वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हम क्षेत्रीय परिषदों को केवल औपचारिक संस्थाओं की बजाय परिवर्तन लाने वाली संस्थाओं के रूप में स्थापित करने में सफल हुए हैं। वर्ष 2004 से 2014 तक क्षेत्रीय परिषदों को केवल 25 बैठकें हुईं, जबकि 2014 से फरवरी 2025 तक, कोविड महामारी के बावजूद कुल 61 बैठकें हुईं, जो इससे पहले के 10 वर्ष के मुकाबले 140 फीसदी अधिक हैं। वर्ष 2004 से 2014 तक क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों में 469 विषयों पर चर्चा हुई, जबकि 2014 से फरवरी 2025 तक 1,541 मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ, जो इससे पहले के 10 वर्ष की तुलना में 170 फीसदी अधिक है। गृह मंत्री ने कहा कि 2004 से 2014 के बीच केवल 448 मुद्दों का निराकरण किया गया, जबकि 2014 से फरवरी 2025 के बीच 1,280 मामलों का निपटारा किया गया। बैठक में महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात के मुख्यमंत्री, दादरा और नगर हवेली व दमन एवं दीव के प्रशासक और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री मौजूद रहे।

महायुति की शानदार जीत से साफ हुआ असली शिवसेना और एनसीपी कौन

शाह ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने विधानसभा चुनावों में महायुति को भारी जीत दिलाकर यह स्पष्ट फैसला दे दिया है कि असली शिवसेना और एनसीपी कौन है। उन्होंने कहा, विधानसभा चुनावों में मिले शानदार समर्थन के लिए वह महाराष्ट्र की जनता के प्रति बहुत आभारी हैं। आपके आशीर्वाद से महायुति सत्ता में आई और भाजपा-शिवसेना-एनसीपी सरकार बनी। ऐतिहासिक जनदेश देकर महाराष्ट्र की जनता ने यह भी स्पष्ट फैसला सुनाया है कि कौन सी शिवसेना और कौन सी एनसीपी असली है।

■ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए शाह ने कहा कि राजग सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए सत्ता में आने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की गई। उन्होंने कहा कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस योजना के तहत 20 लाख परिवारों को अपना पहला घर मिला है। उन्होंने कहा, अगर कोई एक राज्य है जिसे पीएमएवाई के तहत सबसे अधिक घर मिले हैं, तो वह महाराष्ट्र है।

■ केंद्रीय मंत्री शाह ने कहा, आवास के अलावा, पीएम ने यह सुनिश्चित किया है कि हर घर में शौचालय हो, जिससे उनके आत्मसम्मान की रक्षा हुई है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 2029 तक इस योजना के तहत कुल पांच करोड़ घर बनाए जाएंगे, जिनमें से 3.80 करोड़ मकानों का आवंटन हो चुका है।

पुणे में खुलेगा सीआरसीएस का पहला क्षेत्रीय कार्यालय

शाह ने कहा, सहकारी सेवाओं तक पहुंच को बेहतर बनाने के लिए सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) के कार्यालय को एक क्षेत्रीय कार्यालय बनाने का फैसला किया। उन्होंने घोषणा की कि सीआरसीएस का पहला क्षेत्रीय कार्यालय पुणे में खुलेगा। शाह ने इसका पूरा श्रेय केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोले को दिया।

'PM's goal of economic development is incomplete without cooperation'

'पीएम का आर्थिक विकास का लक्ष्य सहकारिता बिना अधूरा'

गृह मंत्री ने कहा- क्षमता अनुसार काम सहकारिता से ही

राज्य ब्यूरो, जागरण • मुंबई : केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री का 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने और अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन डालर तक पहुंचाने का लक्ष्य 'सहकार से समृद्धि' के बिना अधूरा रहेगा। हर व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार काम देना, हर व्यक्ति को देश के विकास के साथ जोड़ना, हर परिवार को समृद्ध बनाना केवल सहकारिता के माध्यम से ही संभव हो सकता है। इसलिए, पीएम मोदी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की है। इस मंत्रालय का मंत्र है-सहकार से समृद्धि। उन्होंने ये बातें जनता सहकारी बैंक के हीरक जयंती समारोह के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कही।

शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने बीते 10 वर्षों में देश के 70 करोड़ गरीबों के कई ऐसे काम कर दिए हैं, जो पीढ़ियों से नहीं हो सके थे। घरों में बिजली, पानी, शौचालय,



पुणे में शनिवार को जनता सहकारी बैंक के अमृत महोत्सव के समापन समारोह के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। साथ में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार तथा एकनाथ शिंदे • एएनआइ

गैस, पांच लाख तक का स्वास्थ्य बीमा और हर व्यक्ति को पांच किलोग्राम तक अनाज। अब इन 70 करोड़ लोगों के सामने समस्या यह है कि वे अपने जिन लक्ष्यों के लिए जीवनभर मेहनत करते थे, वे तो समाप्त हो गए। अब वे देश के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं। यदि पूंजी के बगैर अपने परिवार का विकास करना है और

देश के विकास में योगदान देना है तो इसका एकमात्र रास्ता है सहकारिता। छोटी-छोटी पूंजी मिलाकर बहुत बड़ा काम करना ही सहकारिता है।

शाह ने कहा कि देश में 1,465 सहकारी बैंक हैं। इनमें 460 अकेले महाराष्ट्र में हैं। इन बैंकों के लिए हम अंब्रेला संगठन (सहकारी बैंकों का संरक्षक संगठन) बना रहे हैं, जो सहकारी बैंकों की मदद करेगा।

'The cooperative sector gained momentum due to the efforts of the Centre'

‘केंद्र के प्रयासों से सहकारी क्षेत्र को गति मिली’

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 22 फरवरी।

केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि केंद्र के प्रयासों से पिछले तीन वर्षों में सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा मिला है। पुणे में जनता सहकारी बैंक के हीरक जयंती समारोह के समापन समारोह को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने भारत के सहकारी क्षेत्र को बाजार योग्य बना दिया है।

इसके अलावा, केंद्रीय गृह मंत्री ने पुणे में पश्चिम क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने सहकारी बैंकिंग क्षेत्र से प्रौद्योगिकी अपनाने की अपील की।

शाह ने कहा, ‘पिछले तीन वर्षों में केंद्र ने देश में सहकारी आंदोलन को गति देने का काम किया है।’

Co-operation brought revolution, all co-operative banks are now becoming capable

जनता सहकारी बैंक लिमिटेड का अमृत महोत्सव

सहकारिता ने लाई क्रांति, सभी सहकारी बैंक अब हो रहे सक्षम

एजेसी ► पुणे

सहकारी क्षेत्र के योगदान से हासिल करेंगे लक्ष्य

पुणे में जनता सहकारी बैंक लिमिटेड के अमृत महोत्सव के समापन समारोह में अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की शुरुआत की है। इस मंत्रालय के जरिए देश में कई चीजों में क्रांति आई है। मंत्रालय सहकार से समृद्धि के आदर्श वाक्य पर काम करता है।

जनता सहकारी बैंक भी उसी तर्ज पर काम करता है। उन्होंने कहा कि देश में 1465 शहरी सहकारी बैंक हैं और 400 से अधिक अकेले महाराष्ट्र में हैं। हम एक विशेष संगठन को सक्रिय कर रहे हैं। जो सभी सहकारी बैंकों की हर संभव तरीके से मदद करेगा। इसके लिए 300 करोड़ रुपए का बजट भी मंजूर किया गया है।



अमित शाह ने सहकारिता को लेकर केंद्र की योजनाओं की जानकारी दी। अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने भारत के लिए दो लक्ष्य तय किए हैं। पहला 2047 तक विकसित भारत और 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। ये दोनों लक्ष्य सहकारी क्षेत्र के योगदान से हासिल किए जा सकते हैं।

► सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, राहुल को 'सुनाया'

शाह प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को प्रमाणपत्र वितरित करने के लिए एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं की उपलब्धियों को गिनाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब केंद्र सरकार जनधन खाते खोल रही थी, तब विपक्षी नेता इसका मजाक उड़ा रहे थे। जब हम सभी देशवासियों के जनधन खाते खोल रहे थे, तब राहुल कह रहे थे कि जनधन खाते खोल तो रहे हैं, लेकिन उसमें पैसे कहां से आएंगे? आज हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 10 लाख लोगों को एक ही विलक में पैसा दे दिया है।

'The goal of economic development will remain incomplete without cooperation'

'सहकारिता के बिना अधूरा रहेगा आर्थिक विकास का लक्ष्य'

राज्य व्यूरो, मुंबई • जागरण

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री का 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने और अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य 'सहकार से समृद्धि' के बिना अधूरा रहेगा। हर व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार काम देना, हर व्यक्ति को देश के विकास के साथ जोड़ना, हर परिवार को समृद्ध बनाना केवल सहकारिता के माध्यम से ही संभव हो सकता है। इसलिए, पीएम मोदी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की है। इस मंत्रालय का मंत्र है- सहकार से समृद्धि। उन्होंने ये बातें जनता सहकारी बैंक के हीरक जयंती समारोह के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कही।

शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने बीते 10 वर्षों में देश के 70 करोड़ गरीबों के कई ऐसे काम कर दिए हैं, जो पीढ़ियों से नहीं हो सके थे। घरों में बिजली, पानी, शौचालय, गैस, पांच लाख तक का स्वास्थ्य बीमा और हर व्यक्ति को पांच किलोग्राम तक अनाज। अब इन 70 करोड़ लोगों के सामने समस्या यह है कि वे अपने जिन लक्ष्यों के लिए जीवनभर मेहनत करते थे, वे तो समाप्त हो गए।

केंद्रीय गृह मंत्री शाह बोले, हर व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार काम देना केवल सहकारिता से ही संभव

सहकारिता की शिक्षा विश्वविद्यालयों में दी जाए, इसका भी किया जा रहा है प्रयास



पुणे में शनिवार को पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक में सम्मिलित होने पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। साथ में हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे।

तो अब आगे क्या करना है। अब वे देश के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं। लेकिन, उनके पास पूंजी नहीं है। यदि पूंजी के बगैर अपने परिवार का

विकास करना है और देश के विकास में योगदान देना है तो इसका एकमात्र रास्ता है सहकारिता। छोटी-छोटी पूंजी मिलाकर बहुत बड़ा काम करना ही सहकारिता

कहलाता है। उन्होंने कहा कि हमने पिछले तीन वर्षों में सहकारिता आंदोलन को गति देने का काम किया है। सहकारिता के माडल को बाजार के अनुकूल बनाया है। सहकारिता की शिक्षा विश्वविद्यालयों में दी जाए, इसका प्रयास भी किया जा रहा है।

अमित शाह ने कहा कि देश में इस समय 1,465 सहकारी बैंक हैं। इनमें 460 अकेले महाराष्ट्र में हैं। इन बैंकों के लिए हम एक अंब्रेला संगठन (सहकारी बैंकों का संरक्षक संगठन) बना रहे हैं, जो सहकारी बैंकों की हर प्रकार से मदद करेगा। इस संगठन के लिए 300 करोड़ रुपये की राशि एकत्र करने का काम पूरा हो चुका है। कोई बैंक कहीं कमजोर पड़ेगा, किसी बैंक को तकनीकी दृष्टि से उन्नत होना है या कोर बैंकिंग अपनाना है तो यह शीर्ष संगठन उसे मदद करेगा। देशभर के सभी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, सभी जिला सहकारी बैंक और सभी राज्य कोऑपरेटिव बैंक का अलग से क्लीयरिंग हाउस भी इस अंब्रेला संगठन के माध्यम से ही बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में पहली बार इस प्रकार का क्लीयरिंग हाउस बनाने की कल्पना की गई है। दो साल के अंदर हम इसे पूरा कर देंगे।
